web: www.nyaysakshi.com | पृष्ठ-2 में पढ़ें संपादकीय-खेल-व्यापार-धर्म-खाना खजाना-राशिफल | पृष्ठ-3 में पढ़ें छत्तीसगढ़-प्रादेशिक

दैनिक
न्याय साक्षी
अधिकार से न्याय तक

आवश्यक सूचना

आप सभी को सूचित करते हर्ष हो रहा है, कि न्याससाक्षी अधिकार से न्याय तक का सर्वे का कार्य तेजी से चल रहा है, जल्द ही सर्वे की टीम आपके घर विजिट करेगी, कृपया अपनी प्रति सुरक्षित कराएं।

RNI NO - CHHHIN/2018/76480 | Postal Registration No-055/Raigarh DN CG | रायगढ़, गुरुवार, 14 अप्रैल 2022 | पृष्ठ-4, मूल्य 3 रुपए | वर्ष-04, अंक- 195

महत्वपूर्ण एवं खास

उपराष्ट्रपति की सुरक्षा को लेकर ग्राम प्रहरियों को ने दी गयी ट्रेनिंग

अयोध्या (आरएनएस)। 15 अप्रैल को महामहिम उपराष्ट्रपति वेंकैया नायडू अयोध्या दौरे पर स्पेशल ट्रेन से आ रहे हैं,जिनकी सुरक्षा को लेकर अयोध्या पुलिस तैयारी में लगी हुई है।इसी क्रम में बुधवार को रूदौली कोतवाली में समस्त ग्राम प्रहरियों की कोतवाल शशिकांत यादव ने बैठक किया।बैठक में सुरक्षा को लेकर कोतवाल ने दिशा निर्देश दिया साथ ही सुरक्षा को लेकर ग्राम प्रहरियों को कोतवाली परिसर में ट्रेनिंग दिया।

केरल में कार हादसे में एक परिवार के तीन लोगों की मौत

वायनाड (आरएनएस)। केरल के वायनाड जिला में मीनांगडी के निकट कक्कावायल में एक कार के लॉरी से टकरा जाने के कारण तमिलनाडु के नीलगिरी जिले के पट्टावायल निवासी एक परिवार के तीन सदस्यों की मौत हो गई और तीन साल का एक बच्चा घायल हो गया। पुलिस ने बताया कि मृतकों की पहचान प्रवेश (39), उनकी पत्नी श्रीजिशा (34) और श्रीजिशा की मां प्रेमलता (62) के रूप में हुई है। प्रवेश के पुत्र आरव घायल हुआ है और उसे कोझीकोड के एक निजी अस्पताल में भर्ती कराया गया है। हादसा आज पूर्वाह्न करीब साढ़े 11 बजे हुआ। हादसे के समय यह परिवार कोझिकोड के बालुसेरी में एक शादी समारोह में शामिल होने के बाद कार से पट्टावायल जा रहा था। इसी दौरान सुल्तान बाथेरी से मनंतवाडी की ओर जा रहे लॉरी से कार टकरा गई।

दक्षिण अफ्रीका में बाढ़ से मरने वालों की संख्या बढ़कर हुई 59

जोहान्सबर्ग । दक्षिण अफ्रीका के क्वाजुलु-नताल प्रांत में भारी बारिश और बाढ़ के कारण मरने वालों की संख्या बढ़कर 59 हो गई है। मरने वालों में डरबन शहर के 45 और नीडवेडवे व क्वादुकुजा शहर के 14 लोग हैं। क्वाजुलु-नताल के प्रीमियर सिहले जिकलाला बाढ़ के मद्देनजर यहां आपातकाल घोषित करने का निर्देश दिया है। इससे पहले, क्वाजुलु-नताल में आपातकालीन सेवाओं के प्रवक्ता रॉबर्ट मैकेंजी ने कहा कि राहत और बचाव दल के सदस्य भूस्खलन और बाढ़ प्रभावित इलाकों से लोगों को निकाल रहे हैं। श्री मैकेंजी के अनुसार, यहां की इमारतों, सडक़ों और बिजली के खंभों को बाढ़ से नुकसान पहुंचा है। प्रवक्ता ने स्थानीय निवासियों को इस दौरान घर के अंदर रहने की सलाह दी।

मारियुपोल में एक हजार से अधिक यूक्रेनी नौसैनिकों ने किया आत्मसमर्पण

कीव। रूस के चेचन्या गणराज्य के नेता रमजान कादिरोव ने मारियुपोल में 1,000 से अधिक यूक्रेनी सेनाओं के आत्मसमर्पण किए जाने की जानकारी दी है। कादिरोव ने टेलीग्राम पर लिखा, यूक्रेनी सशस्त्र बलों के 1,000 से अधिक नौसैनिकों ने आज मारियुपोल में आत्मसमर्पण किया है। इनमें से सैकड़ों घायल हैं। यही उनकी तरफ से उठाया गया सही कदम है। पूर्वी यूक्रेन के डोनेट्स्क और लुहान्सक को आजाद देश के तौर पर मान्यता देने के बाद यूक्रेनी सेना के द्वारा यहां लगातार किए जा रहे हमलों से सुरक्षा के मद्देनजर रूस ने 24 फरवरी को यूक्रेन में विशेष सैन्य अभियान की शुरुआत की थी। इस हमले को लेकर रूसी रक्षा मंत्रालय के प्रवक्ता ने कहा था कि विशेष सैन्य अभियान का मकसद यूक्रेनी सैन्य बुनियादी ढांचे को निशाना बनाना है। यूक्रेन पर कब्जा जमाने का उनका कोई इरादा नहीं है।

पहाड़ी से टकराकर लोगों से भरा ट्रक पलटा, 16 की मौत; कई गंभीर रूप से घायल

जकार्ता। इंडोनेशिया के पूर्वी प्रांत पश्चिमी पापुआ में एक ट्रक दुर्घटना में कम से कम 16 लोगों की मौत हो गई और छह अन्य गंभीर रूप से घायल हो गए। प्रांत के मनोकवारी जिले में खोज और बचाव कार्यालय के एक प्रेस अधिकारी मुहम्मद खैरुल बस्यार ने इसकी जानकारी दी है। अधिकारी ने बताया कि यह घटना स्थानीय समयानुसार तडक़े करीब तीन बजे हुई जब 29 लोगों को ले जा रहा ट्रक पेंगुनुनगन अरफाक जिले के मिन्याम्बो उप जिले में एक ढलान वाली सडक़ से गुजर रहा था। ट्रक सडक़ के किनारे एक पहाड़ी से टकरा गया, जिसमें 13 लोगों की घटनास्थल पर ही मौत हो गई और तीन अन्य की अस्पताल में मौत हो गई और छह अन्य गंभीर रूप से घायल हो गए।

केन्द्रीय मंत्रिमंडल ने भारत और जापान के बीच एक सहयोग ज्ञापन पर हस्ताक्षर को मंजूरी दी

नई दिल्ली (आरएनएस)। प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी की अध्यक्षता में केन्द्रीय मंत्रिमंडल ने आज विकेन्द्रीकृत घरेलू अपशिष्ट जल प्रबंधन के क्षेत्र में जल संसाधन, नदी विकास एवं गंगा संरक्षण विभाग (डीओडब्ल्यूआर, आरडी एंड जीआर), जल शक्ति मंत्रालय और जापान के पर्यावरण मंत्रालय के बीच हस्ताक्षरित एक सहयोग ज्ञापन (एमओसी) को कार्योत्तर मंजूरी दे दी है।

एक प्रबंधन परिषद (एमसी) का गठन किया जाएगा, जो सहयोग की विस्तृत गतिविधियों को निर्धारित करके और इन गतिविधियों की प्रगति की निगरानी के माध्यम से इस सहयोग ज्ञापन (एमओसी) के कार्यान्वयन के लिए जिम्मेदार होगी।

इस सहयोग ज्ञापन (एमओसी) के माध्यम से विकेन्द्रीकृत घरेलू अपशिष्ट जल प्रबंधन और जोहकासौ प्रौद्योगिकी का उपयोग करके शोधित अपशिष्ट जल के प्रभावी दोबारा उपयोग जैसे क्षेत्रों में जापान के साथ सहयोग बेहद उपयोगी साबित होगा। अपशिष्ट जल के प्रबंधन से संबद्ध यह विकेन्द्रीकृत जोहकासौ प्रणाली जल जीवन मिशन के कवरेज के तहत आनेवाली बस्तियों से निकले अपशिष्ट/गंदे पानी के प्रबंधन साथ-साथ इस मिशन के तहत ताजे पानी के स्रोतों की निरंतरता के अलावा नमामि गंगे कार्यक्रम के तहत इसी तरह की स्थितियों के लिए बेहद प्रभावकारी हो सकती है। जापान के साथ सहयोग का यह कदम शहरी स्थानीय निकायों (यूएलबी) को अपशिष्ट जल के शोधन की जटिल समस्या से निपटने के लिए बेहतर योजना बनाने में मदद करेगा।

इस सहयोग ज्ञापन (एमओसी) के तहत दोनों पक्षों पर कोई वित्तीय दायित्व नहीं होगा। इस एमओसी के तहत विभिन्न गतिविधियों को सुविधाजनक बनाने के लिए, मामले– विशेष में अन्य बातों के अलावा संबंधित क्षेत्रों से जुड़े विस्तृत विनिर्देशों के साथ-साथ अन्य प्रासंगिक मुद्दों जैसे कि जरूरी होने पर ऐसे मामले-विशेष के कार्यक्रम एवं परियोजना की वित्तीय व्यवस्था को कवर करते हुए पूर्व-व्यवहार्यता रिपोर्ट, व्यवहार्यता रिपोर्ट और विस्तृत परियोजना रिपोर्ट जैसे विस्तृत दस्तावेज तैयार किए जा सकते हैं।

विकेन्द्रीकृत घरेलू अपशिष्ट जल प्रबंधन के क्षेत्र में जल संसाधन, नदी विकास एवं एवं गंगा संरक्षण विभाग (डीओडब्ल्यूआर, आरडी एंड जीआर), जल शक्ति मंत्रालय (एमओजेएस) और जापान के पर्यावरण मंत्रालय के बीच एक सहयोग ज्ञापन (एमओसी) पर 19 मार्च 2022 को हस्ताक्षर किए गए। दोनों देशों के बीच समानता और पारस्परिक लाभ के सिद्धांतों के आधार पर सार्वजनिक जल क्षेत्रों में जलीय पर्यावरण के संरक्षण और सार्वजनिक स्वास्थ्य में सुधार के उद्देश्य से विकेन्द्रीकृत घरेलू अपशिष्ट जल प्रबंधन के क्षेत्र में सहयोग को बढ़ावा देने के लिए इस सहयोग ज्ञापन (एमओसी) पर हस्ताक्षर किए गए थे।

विकेन्द्रीकृत घरेलू अपशिष्ट जल प्रबंधन की क्षमता को मजबूत करने, उसे सुगम बनाने और विकसित करने के उद्देश्य से भारत गणराज्य के जल संसाधन, नदी विकास एवं एवं गंगा संरक्षण विभाग (डीओडब्ल्यूआर, आरडी एंड जीआर), जल शक्ति मंत्रालय (एमओजेएस) और जापान के पर्यावरण मंत्रालय के बीच इस सहयोग ज्ञापन (एमओसी) पर हस्ताक्षर किए गए। सहयोग का दायरा ज्यादातर विकेन्द्रीकृत घरेलू अपशिष्ट जल प्रबंधन और शोधित अपशिष्ट जल का प्रभावी दोबारा उपयोग पर केंद्रित है। इस सहयोग ज्ञापन (एमओसी) के तहत सहयोग के विभिन्न स्वरूप पारस्परिक सहयोग, जिसमें संगोष्ठियों, सम्मेलनों और क्षमता निर्माण के माध्यम से विकेन्द्रीकृत घरेलू अपशिष्ट जल प्रबंधन से संबंधित सूचना और विशेषज्ञता के आदान-प्रदान शामिल हो सकते हैं लेकिन पारस्परिक हित के क्षेत्रों तक ही सीमित नहीं रहेंगे, को प्रोत्साहित करेंगे व उसे सुगम बनायेंगे।

इस सहयोग ज्ञापन (एमओसी) के तहत विभिन्न गतिविधियों को सुविधाजनक बनाने के लिए, मामले – विशेष में अन्य बातों के अलावा संबंधित क्षेत्रों से जुड़े विस्तृत विनिर्देशों के साथ-साथ अन्य प्रासंगिक मुद्दों जैसे कि जरूरी होने पर ऐसे मामले-विशेष के कार्यक्रम एवं परियोजना की वित्तीय व्यवस्था को कवर करते हुए पूर्व-व्यवहार्यता रिपोर्ट, व्यवहार्यता रिपोर्ट और विस्तृत परियोजना रिपोर्ट जैसे विस्तृत दस्तावेज तैयार किए सकते हैं। दोनों पक्ष एक प्रबंधन परिषद (एमसी) की स्थापना करेंगे, जो सहयोग की विस्तृत गतिविधियों को निर्धारित करके और इन गतिविधियों की प्रगति की निगरानी के माध्यम से इस सहयोग ज्ञापन (एमओसी) के कार्यान्वयन के लिए जिम्मेदार होगी।

नरवणे ने स्वदेश निर्मित विशिष्ट वाहनों को सेवा में किया शामिल

पुणे (आरएनएस)। थल सेना प्रमुख जनरल एम. एम. नरवणे ने बॉम्बे इंजीनियर ग्रुप (बीईजी) एंड सेंटर में आयोजित एक समारोह में स्वदेश निर्मित विशिष्ट वाहनों को सेवा में शामिल किया।

श्री नरवणे ने आज जिन वाहनों को सेवा में शामिल किया, च्कि रिएक्शन फाइटिंग व्हीकल मीडियम (क्यूआरएफवी), इन्फैंट्री प्रोटेक्टेड मोबिलिटी व्हीकल (आईपीएमवी), टाटा एडवांस्ड सिस्टम लिमिटेड (टीएएसएल) द्वारा विकसित अल्ट्रा लॉन्ग रेंज ऑब्जर्वेशन सिस्टम और भारत फोर्ज द्वारा विकसित मोनोकोक हल मल्टी रोल माइन प्रोटेक्टेड आर्मर्ड व्हीकल्स का पहला सेट शामिल है।

इस मौके पर उन्होंने भारत सरकार की आत्मनिर्भर भारत पहल को मजबूत करने और पिछले दशकों से भारतीय सेना के साथ निरंतर जुड़ाव के लिए टाटा और भारत फोर्ज की सराहना की। एक आधिकारिक बयान में बताया गया कि जनरल नरवणे के साथ वाइस चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ लेफ्टिनेंट जनरल मनोज पांडे भी पुणे के दो दिवसीय दौरे पर हैं।

माता वैष्णों देवी भक्तों के लिए आई खुशखबरी, कटरा से अर्धकुआंरी तक मिलेगी रोपवे की सुविधा

जम्मू (आरएनएस)। जम्मू में 700 साल पुराने माता वैष्णो देवी मंदिर में तीर्थयात्रा की सुविधा के लिए श्राइन बोर्ड ने कटरा और अधकुंवारी के बीच 1,281 मीटर लंबे रोपवे के निर्माण के बहुप्रतीक्षित प्रस्ताव को मंजूरी दे दी। श्री माता वैष्णो देवी श्राइन बोर्ड की 69वीं बैठक में प्रस्ताव को मंजूरी दी गई, जिसकी अध्यक्षता बोर्ड के अध्यक्ष जम्मू-कश्मीर के उपराज्यपाल मनोज सिन्हा ने की। कटरा और अधकुंवारी के बीच का ट्रेक 6 किमी है। दिल्ली स्थित श्राइन बोर्ड के सदस्य के.के. शर्मा ने एआईएमआईएल फार्मास्युटिकल्स लिमिटेड के विवरण साझा करते हुए आईएएनएस को बताया कि इस प्रस्ताव पर लंबे समय से चर्चा चल रही थी। उन्होंने कहा, वास्तव में, 2012 में पहली बार 51वीं बैठक में बोर्ड ने रोपवे की संभावनाओं का पता लगाने के लिए राइट्स लिमिटेड एक रेलवे उपक्रम के साथ एक अध्ययन करने का निर्णय लिया था। राइट्स ने 2017 में बोर्ड को अपनी रिपोर्ट पेश की, जिसमें पाया गया कि यह कटरा और अधकुंवारी के बीच रोपवे के निर्माण के लिए उपयुक्त है। तब से यह प्रस्ताव लगातार लंबित था, जिसे मंगलवार को हुई नवगठित बोर्ड की पहली बैठक में मंजूरी दे दी गई। सबसे पवित्र हिंदू मंदिरों में से एक वैष्णो देवी, जम्मू जिले के कटरा शहर में स्थित है। मंदिर कटरा से लगभग 12 किमी दूर 5,200 फीट की ऊंचाई पर स्थित है।

प्रस्ताव के अनुसार 1,281.20 मीटर लंबे रोपवे का निर्माण अधिकतम 590.75 मीटर की ऊंचाई के साथ किया जाएगा। इसकी क्षमता आठ लोगों की क्षमता वाले प्रत्येक केबिन के साथ प्रति घंटे एक तरफ 1,500 लोगों को ले जाने की होगी। जबकि इसके निर्माण का अनुमान 94.23 करोड़ रुपये है, राइट्स का कहना है कि परिचालन लागत का 63 प्रतिशत वसूल किया जा सकता है यदि प्रति यात्री यात्रा शुल्क 200 रुपये रखा जाए। शर्मा ने कहा कि निर्माण जल्द शुरू होगा। तीर्थस्थल पर तीर्थयात्रियों की संख्या 2021 में 55.77 लाख से अधिक थी, जबकि पिछले वर्ष कोरोनोवायरस महामारी के कारण 17 लाख थी।

भारत ने राशन योजना से पूरे विश्व को एक नई सोच का परिचय दिया : पीयूष गोयल

नई दिल्ली (आरएनएस) । भारतीय जनता पार्टी अपने स्थापना दिवस के अवसर पर सामाजिक न्याय पखवारा पूरे देश में मना रही है। १३ अप्रैल को गरीब कल्याण योजना के रूप में भारतीय जनता पार्टी देश के हर एक जिले के कार्यालय में मना रही है। गरीब कल्याण योजना के बारे में जानकारी देते हुए दिल्ली भाजपा मुख्यालय में केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल ने बताया कि भारत ने पूरे विश्व को एक नई सोच का परिचय दिया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जिस प्रकार गरीब कल्याण योजना का पूरे देश में कार्य किया है इस कार्य की चर्चा पूरे विश्व में हो रही है। गरीब कल्याण को केंद्र बिंदु में रखते हुए समय-समय पर गरीब कल्याण योजना का विस्तार किया और देशवासियों एवं पूरे विश्व को अपने संवेदनशील नेतृत्व और चरित्र के बारे में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने दर्शाया । इस शताब्दी के सबसे बड़े संकट कोरोनावायरस के बावजूद भारत एक ऐसा देश बनकर उभरा है जिसमें एक भी गरीब परिवार के घर में चूल्हा न जला हो ऐसी स्थिति उत्पन्न नहीं हुई है। केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल ने कहा कि कोरोनावायरस संकट के लगभग २५ महीने के अंतराल के बीच प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना के अंतर्गत ८० करोड़ देशवासियों को प्रतिमाह ५ किलो अनाज मुफ्त देने का काम प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में किया जा रहा है। केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल ने कहा कि प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना के अंतर्गत २५ महीनों में १००००० मीट्रिक टन अनाज गरीबों तक पहुंचाया गया है। गोयल ने कहा कि यह विश्व का सबसे बड़ा खाद्य सुरक्षा का प्रोग्राम भारत में चलाया गया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हमेशा उन गरीबों के बारे में सोचते हैं और समाज के हर उस व्यक्ति के बारे में सोचते हैं जो पिछले ६० सालों से देश के चुनाव का लाभ नहीं उठा पा रहा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की दूरदर्शिता का नतीजा है की वन नेशन वन राशन कार्ड पीएम की एक कल्पना थी कि कैसे हम देश के ८० करोड़ लाभार्थियों को टेक्नोलॉजी से जोडक़र उन्हें देश में कहीं भी अनाज प्राप्त करने की सुविधा देने की प्रक्रिया प्रारंभ की जाए। कोरोनावायरस के समय ऐसा देखा गया कि गांव के मजदूर कहीं दूसरे जगह कार्य कर रहे हैं और वह इस महामारी के संकट में फंसे हुए थे तो वहां भी हर महीने ५ किलो राशन उनको आसानी से मिल जाया करती थी। पीयूष गोयल ने कहा कि लगभग ऐसे ६५ करोड़ पोर्टेबिलिटी ट्रांसेक्शन से लोगों ने अपने अन्न को अपने घर की जगह कहीं और से लिया है। गोयल ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के कार्यों को अंतरराष्ट्रीय पटल पर भी सराहना मिली है। गोल ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने हमेशा कहा है कि गरीबों को अनाज देना हमारी सरकार के लिए कभी भी बोझ नहीं है। गोयल ने कहा कि इस योजना को चुनाव से जोडक़र देखना एक तरह से गरीबों को मजाक बनाने जैसा है। केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल ने कहा कि हमारे पास अभी ५०० लाख टन स्टोर है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कभी भी किसी राज्य के साथ ऐसा नहीं किया है कि वहां के लोगों को आना ज्यादा या कम दिया जाए इस योजना को पूरे देश में एक साथ लागू किया जाता है और एक साथ ही वितरण किया जाता है ताकि देश के गरीबों के घर का चूल्हा कभी भी बंद ना हो। बोल ने कहा कि हमारी सरकार की ही खासियत है कि पहले हम २ लाख टन भी और निर्यात करते थे लेकिन अब हम २० से ३० लाख टन निर्यात किया करते हैं।

न्यूयॉर्क में दो सिखों पर घातक हमला, पगड़ी उतारी, डंडे से पीटा, एक आरोपी गिरफ्तार

न्यूयॉर्क । न्यूयॉर्क में क्वींस के रिचमंड हिल इलाके में दो सिखों पर घातक हमला हुआ है। न्यूयॉर्क पुलिस विभाग हेट क्राइम टास्क फोर्स के अनुसार, हमले में दो लोग शामिल थे, जिसमें एक को गिरफ्तार कर लिया गया और दूसरे की तलाश जारी है। एक हफ्ते के अंदर यह इस प्रकार की दूसरी घटना है। इससे पहले एक बुजुर्ग सिख पर भी इसी तरह बेरहमी से हमला किया गया था। हमलावरों ने दोनों सिखों को उसी इलाके में लूटा, जहां 72 वर्षीय निर्मल सिंह पर अकारण हमला किया गया था।

न्यूयॉर्क में भारत के महावाणिज्य दूतावास ने हमले की निंदा करते हुए इसे निंदनीय करार दिया और कहा कि वे उस पुलिस के संपर्क में हैं जो इस घटना की जांच कर रही है। भारत के महावाणिज्य दूतावास ने ट्वीट कर लिखा, न्यूयॉर्क के रिचमंड हिल्स में आज दो सिख सज्जनों पर हमला निंदनीय है। हमने मामले में स्थानीय अधिकारियों और न्यूयॉर्क शहर के पुलिस विभाग से संपर्क किया है। पता चला है कि पुलिस में शिकायत दर्ज की गई है और एक व्यक्ति को गिरफ्तार किया गया है। हम कम्युनिटी सदस्यों के संपर्क में हैं। पीडितों को हर संभव सहायता देने के लिए तैयार हैं। दो संदिग्धों ने पुरुषों को डंडे से मारा और उनकी पगड़ी उतार दी। विडंबना यह है कि यह हमला सिख संगठनों द्वारा न्यूयॉर्क में एकजुटता रैली आयोजित करने के लगभग 24 घंटे बाद हुआ।

केन्द्रीय मंत्रिमंडल ने 1957 के तहत अधिग्रहित भूमि के उपयोग के लिए नीति को मंजूरी दी

नई दिल्ली (आरएनएस)। खनन की जा चुकी या व्यावहारिक रूप से खनन के लिए अनुपयुक्त भूमि के उपयोग को सुविधाजनक बनाने और कोयला क्षेत्र में निवेश तथा रोजगार सृजन को बढ़ाने के उद्देश्य से, प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी की अध्यक्षता में केंद्रीय मंत्रिमंडल ने कोयला युक्त क्षेत्र (अधिग्रहण एवं विकास) अधिनियम, 1957 [सीबीए अधिनियम] के तहत अधिग्रहित भूमि के उपयोग के लिए नीति को मंजूरी दी है। इस नीति में कोयला और ऊर्जा से संबंधित अवसंरचना के विकास तथा स्थापना के उद्देश्य से ऐसी भूमि के उपयोग का प्रावधान है।

सीबीए अधिनियम में किसी भी ऋणभार से मुक्त, कोयला युक्त भूमि के अधिग्रहण और इसे सरकारी कंपनी में निहित करने का प्रावधान है। अनुमोदित नीति, सीबीए अधिनियम के तहत अधिग्रहित भूमि के निम्न प्रकार के उपयोग के लिए स्पष्ट नीतिगत रूपरेखा प्रदान करती है:

कोयला खनन गतिविधियों के लिए भूमि; अब उपयुक्त नहीं है या आर्थिक रूप से व्यावहारिक नहीं है; या

(ब) जिन भू-क्षेत्रों से कोयले का खनन/कोयला निकालने का कार्य हो चुका है और ऐसी भूमि को फिर से प्राप्त किया गया है।

सरकारी कोयला कंपनियां, जैसे कोल इंडिया लिमिटेड (सीआईएल) और इसकी सहायक कंपनियां, सीबीए अधिनियम के तहत अधिग्रहित इन भू-क्षेत्रों की मालिक बनी रहेंगी और यह नीति, केवल नीति में दिए गए निर्दिष्ट उद्देश्यों के लिए ही, भूमि को पट्टे पर देने की अनुमति देती है। कोयला और ऊर्जा संबंधी अवसंरचना विकास गतिविधियों के लिए सरकारी कोयला कंपनियां संयुक्त परियोजनाओं में निजी पूंजी लगा सकती हैं।

जिस सरकारी कंपनी के पास भूमि है, वह ऐसी भूमि को नीति में दी गई निश्चित अवधि के लिए पट्टे पर देगी और पट्टे के लिए संस्थाओं का चयन एक पारदर्शी, निष्पक्ष और प्रतिस्पर्धी बोली प्रक्रिया और तंत्र के माध्यम से किया जाएगा, ताकि अधिकतम मूल्य प्राप्त किया जा सके। निम्नलिखित गतिविधियों के लिए भू-क्षेत्रों पर विचार किया जाएगा:

कोल वाशरी स्थापित करना;

कन्वेयर सिस्टम स्थापित करना;

कोल हैंडलिंग प्लांट स्थापित करना;

1. रेलवे साइडिंग का निर्माण;

1. सीबीए अधिनियम या अन्य भूमि अधिग्रहण कानून के तहत भूमि-अधिग्रहण के कारण परियोजना प्रभावित परिवारों का पुनर्वास और स्थान-परिवर्तन पुनर्वास;

1. ताप आधारित और नवीकरणीय विद्युत परियोजनाओं की स्थापना करना;

1. प्रतिपूरक वनरोपण सहित कोयला विकास संबंधी अवसंरचना की स्थापना या प्रावधान करना;

1. मार्ग का अधिकार प्रदान करना;

. कोयला गैसीकरण और कोयले से रसायन संयंत्र; और

. ऊर्जा से संबंधित अवसंरचना की स्थापना या प्रावधान करना।

जिन भू-क्षेत्रों से खनन किया जा चुका है या जो कोयला खनन के लिए व्यावहारिक रूप से अनुपयुक्त हैं, उन पर अनधिकृत अतिक्रमण होने की संभावना रहती है और सुरक्षा तथा रख-रखाव पर अनावश्यक व्यय करना पड़ता है। अनुमोदित नीति के तहत, सरकारी कंपनियों से स्वामित्व को बिना हस्तांतरण किये विभिन्न कोयला और ऊर्जा संबंधी अवसंरचना की स्थापना से बड़ी संख्या में प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रोजगार का सृजन होगा। अन्य उद्देश्यों के लिए गैर-खनन योग्य भूमि का फिर से उपयोग शुरू होने पर सीआईएल को अपनी परिचालन लागत को कम करने में भी मदद मिलेगी, क्योंकि यह कंपनी, निजी क्षेत्र के साथ साझेदारी में विभिन्न व्यवसाय मॉडल को अपनाकर कोयले से संबंधित अवसंरचना और अन्य परियोजनाओं जैसे सौर संयंत्र को अपनी जमीन पर स्थापित करने में सक्षम होगी। यह कोयला गैसीकरण परियोजनाओं को व्यावहारिक बनाएगा, क्योंकि कोयले को दूर स्थानों पर ले जाने की आवश्यकता नहीं होगी।